

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी वाडमेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एसआदेश

दिनांक 20.07.2022

उपरिस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दर्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित होने से अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांटगण ने जानबूझकर कोई देरी व लाप. रवाही नहीं की है ज्ञान के तुरन्त बाद तत्परता से न्यायालय में पेश होकर प्रार्थना-पत्र नकल पाने का पेश कर नकलें दिनांक 26.04.2022 को प्राप्त कर व अन्य नकले भू अभिलेख से प्राप्त कर व सम्यक तत्परता के साथ वकील मुकर्रर कर अपील तैयार कर पेश की जा रही है। न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न लिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2014(1) Page 523

RLW 2005(1) Page 433

RLW 2008(2) Page 1185

RLW 2008(2) Page 1142

RLW 2005(2) Page 397

RLW 2006(1) Page 324

[Signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर

रेस्पोंडेंट्स अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध तकरीबन 06 वर्ष बाद अपीलांतगण द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होंगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। कब्जा अपीलांत का है तो भी स्थगन से अपीलांतगण को कोई हानि नहीं हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंट्स के पक्ष में है। अतः अपीलांतगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांत की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांतगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

Jain
(पतिष्ठा प्रिन्सिपल)
राजस्व अपील प्रमाधिकारी
वाइमेर